शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार मीमांसा
मध्यप्रदेश

सीबीएसई ने चार माह पहले 30% कोर्स कम किया, एमपी बोर्ड तो फैसला ही नहीं ले सका, 50 लाख विद्यार्थी प्रभावित

एमपी बोर्ड ने पढ़ाई तो ऑनलाइन कर दी, लेकिन कोर्स में कटौती करना भूल गया

कोर्स पूरा होने के बाद फैसला लिया तो विद्यार्थी से स्कूल, शिक्षक तक का नुकसान

विद्यार्थी बोले- अभी कोर्स कम हुआ तो ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च और समय बचेगा

मेरी पढ़ाई

इंदौर • डीबी स्टार

जिले में नौवीं से 12वीं तक पढ़ने वाले डेढ़ लाख सहित प्रदेश के करीब 50 लाख विद्यार्थी चार माह से कोर्स कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संकट के कारण सीबीएसई बोर्ड चार महीने पहले ही अपना 30 फीसदी कोर्स कम चुका है, लेकिन एमपी बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मंडल) के जिम्मेदार अधिकारियों की नींद अब तक नहीं खुली है। यदि परीक्षा के समय कोर्स कम किया तो उसका लाभ नहीं होगा। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि अभी फैसला लेता है तो इससे ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च और समय दोनों बच सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव रश्मी अरुण शमी का कहना है कि इस मामले में बोर्ड अधिकारी ही तय करेंगे। वहीं, बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा का कहना है कि नया सिलेबस जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।

कोरोना के कारण नौ महीने से देशभर के स्कूल-कॉलेज से कोचिंग संस्थान तक बंद हैं। कॉलेज स्तर तक जनरल प्रमोशन से लेकर जरूरी परीक्षाएं 'एग्जाम फ्रॉम होम' पैटर्न पर ली गई हैं। शिक्षण संस्थान बंद होने के कारण ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग भी वाट्स एप और दूरदर्शन से पढ़ाने के साथ ही मोहल्ला कक्षा लगा रहा है। देशव्यापी संकट को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 7 जुलाई को नौवीं से 12वीं तक सभी कक्षाओं का 30 प्रतिशत कोर्स कम कर दिया, ताकि विद्यार्थियों से पढ़ाई का बोझ कुछ हद तक कम हो सके। एमपी बोर्ड को भी 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष का कोर्स कम करना है, लेकिन उसने अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस लेटलतीफी के कारण चारों कक्षाओं के विद्यार्थी पूरा कोर्स पढ़ने के मजबूर हैं।

इस बार जिले में 50 हजार विद्यार्थी केवल 10वीं कक्षा के होंगे

वर्ष 2020-21 में एमपी बोर्ड की परीक्षा में इंदौर जिले से 10वीं कक्षा के 50 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। पिछले साल 45 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। इस बार नए-पुराने मिलाकर आंकड़ा 50 हजार तक जाएगा। इसी तरह नौवीं, 11वीं और 12वीं मिलाकर जिले में डेढ़ लाख विद्यार्थी हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की परीक्षा देंगे। प्रदेश के छोटे-बड़े सभी 52 जिलों के विद्यार्थियों का आंकड़ा करीब 50 लाख होगा।

विद्यार्थियों की चिंता- परीक्षा में अब समय कम और कोर्स ज्यादा

एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण छह महीने ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है। स्कूल अब तक नहीं खुले हैं। कोचिंग क्लास भी बंद होने से ट्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में 10वी और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई शिक्षक के बिना मुमकिन नहीं है। एमपी बोर्ड यदि जुलाई-अगस्त में कोर्स कम देता तो हमारा बोझ कम हो जाता। अब भी वक्त है। यदि कोर्स कम करने की घोषणा होती है तो कम से कम कुछ चैप्टर कम करना पड़ेंगे। इससे हमें जरूरी पाठ पढ़ने का अधिक समय मिल सकेगा। क्योंकि दिवाली बाद परीक्षा का माहौल बनने लगेगा। ऐसे में यदि स्कूल खुल भी गए तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकेगी। परीक्षा में दिन कम बचेंगे और कोर्स काफी रहेगा तो सेल्फ स्टडी ही करना होगा।

अब तक कोर्स कम करने की सूचना ही नहीं मिली

सीबीएसई का कोर्स कम होने की जानकारी जरूर है, लेकिन एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को फिलहाल पूरा कोर्स ही पढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में जब भी आदेश जारी होगा, हम भी शासकीय और निजी स्कूलों को सूचित कर देंगे।
संजय गोयल, डीईओ इंदौर

बोर्ड का नया सिलेबस जल्द वेबसाइड पर होगा अपलोड

एमपी बोर्ड ने भी अपना कोर्स कम कर लिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी के लिए कोर्स में कटौती की जानकारी एक-दो दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में जिला स्तर पर सूचना दे रहे हैं।
बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक एमपी बोर्ड

कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठे विद्यार्थी

भास्कर संवाददाता | सागर

होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के इंटर्नशिप विद्यार्थी प्रबंधन की मनमानी और नियम विरुद्ध कराए जा रहे क्रियाकलापों के विरोध में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस दौरान विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा सीसीएच के नियम के विरुद्ध जाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कॉलेज में ना कोई पेशेंट आता है और ना ही पेशेंट उन्हें दिखाए जाते हैं। कंप्यूटर में फर्जी मरीजों के नाम की ओपीडी और आईपीडी दर्ज की जा रही है। इसका विरोध करने पर प्रबंधन द्वारा धमकाया जा रहा है। इसके अलावा डिग्री निरस्त करने की चेतावनी दी जा रही है। बीएचएमएस का कोर्स पूरा होने की समयावधि 5 साल 6 माह है।

पिछले साल सभी छात्रों के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है। विद्यार्थी लगातार कॉलेज जाकर डिग्री पूरी करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद भी उन्हें सीसीएच के नियमों का हवाला देकर धमकाया जा रहा है। सवाल पूछने पर इंटर्नशिप निरस्त करने की बात कही जा रही है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

नया विचार

4Gotten Generation के नाम एक खुला खत, ताकि वे भारत के लिए सही मुद्दों पर सोचें

युवा फालतू फोन से छुटकारा पाएं और भारत को अमीर बनाएं

चेतन भगत

अंग्रेजी के उपन्यासकार

chetan.bhagat@gmail.com

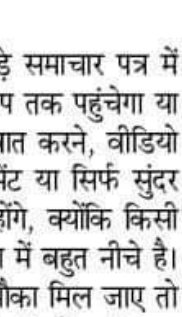

प्रिय मित्रो,

मैं नहीं जानता कि एक बड़े समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बावजूद, यह पत्र आप तक पहुंचेगा या नहीं। आपमें से तमाम लोग फोन पर बात करने, वीडियो देखने, चैटिंग, सोशल मीडिया पर कमेंट या सिर्फ सुंदर सेलेब्रिटीज की फीड देखने में व्यस्त होंगे, क्योंकि किसी आर्टिकल को पढ़ना आपकी प्राथमिकता में बहुत नीचे है। हालांकि, अगर आपको इसे पढ़ने का मौका मिल जाए तो कृपया पूरा पढ़ें। आप फोन पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। हां, आप भारत के इतिहास की पहली युवा पीढ़ी हो, जिसे स्मार्टफोन व सस्ता डेटा उपलब्ध है और आप हर दिन घंटों इस पर बिता रहे हो। अपना स्क्रीन टाइम देखें, जो युवाओं के लिए अक्सर औसत 5-7 घंटे है। रिटायर अथवा स्थापित लोग अपने गैजेट्स पर इतना समय व्यतीत कर सकते हैं। एक युवा, जिसे अभी अपनी जिंदगी बनानी है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पांच घंटे आपके उत्पादकता वाले कामकाजी समय का एक तिहाई है। फोन की लत आपकी जिंदगी का एक हिस्सा खा रही है। यह कॅरिअर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही है और दिमाग खराब कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा था तो आपकी पीढ़ी 4Gotten generation (भूली हुई पीढ़ी) बन जाएगी, यानी एक पूरी पीढ़ी जिसे 4G की लत है, जो लक्ष्यहीन है और देश के बारे में अनभिज्ञ है। फोन की लत के यह तीन टॉप नकारात्मक प्रभाव हैं-

पहला, निश्चित ही यह समय की बर्बादी है, जिसका इस्तेमाल जीवन में अधिक उत्पादक चीजें पर हो सकता है। फोन पर लगने वाले तीन घंटे बचाकर उन्हें फिटनेस, कुछ सीखने, पढ़ने, अच्छी नौकरी तलाशने, बिजनेस खोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

दूसरे, फिजूल कंटेंट देखने से आपका समझ संबंधी दिमाग कमजोर होता है। दिमाग के दो क्षेत्र होते हैं- ज्ञान (समझ) संबंधी और भावनात्मक। एक अच्छा दिमाग वह है, जिसमें दोनों अच्छे से काम करते हैं। जब आप कबाड़ देखते हैं तो ज्ञान संबंधी दिमाग कम इस्तेमाल होता है। जल्द ही आपकी सोचने व तर्क सहित बहस की क्षमता कम हो जाती है। आप किसी बात के गुण-दोष देखने व सही फैसले में विफल होने लगते हैं। आप सिर्फ भावनात्मक दिमाग से काम करते हैं। सोशल मीडिया पर स्थायी गुस्सा, ध्रुवीकरण, किसी सेलेब्रिटी या राजनेता के धुर प्रशंसक या उससे घृणा और किसी टीवी एंकर की लोकप्रियता, ये सभी उस पीढ़ी की ओर इशारा करते हैं, जिसका नियंत्रण भावनात्मक दिमाग के हाथ में है। इसलिए वे जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाते। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने दिमाग को सुन्न न होने दें और उसे उत्पादक कामों में लगाए रखें।

तीसरा, स्क्रीन पर कई घंटे बिताने से मनोबल व ऊर्जा का क्षय होता है। जिंदगी में सफलता लक्ष्य निर्धारित करने, प्रेरित रहने और मेहनत से मिलती है। जबकि स्क्रीन देखना आलसी बनाता है। आप में विफलता का डर बैठ जाता है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता कि आप काम कर सकते हैं। इसलिए आप कारण तलाशने लगते हैं कि जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिली। आप दुश्मन तलाशने लगते हैं- आज के बुरे नेता, पुराने बुरे नेता, मुस्लिम, बॉलीवुड और उसका भाई-भतीजावाद, अमीर, प्रसिद्ध लोग या कोई और विलेन जिसकी वजह से आपकी जिंदगी वह नहीं हो सकी जो हो सकती थी। हां, सिस्टम अन्यायपूर्ण है। लेकिन सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से मदद नहीं मिलेगी। अपने ऊपर काम करने से मिलेगी। क्या आप अपना अधिकतम कर रहे हैं? इस फोन को तब तक खुद से दूर रखें जब तक कुछ बन नहीं जाते। विजेता अन्याय के खिलाफ भी रास्ता निकाल लेते हैं। आप भी निकाल सकते हैं।

क्या आपको कॅरिअर पर फोकस करना चाहिए या कभी खत्म न होने वाले हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर? आप अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हैं या बॉलीवुड की साजिशों को हल करना?

यह आप पर है कि आप भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। उस पीढ़ी के बारे में सोचें जिसने हमें आजादी दिलाई। मुझे आज भी मंडल कमीशन का विरोध या 2011 का अन्ना आंदोलन याद है। युवा राष्ट्रीय मुद्दों की परवाह करता था। क्या आज का युवा इस बात की परवाह करता है कि हमें असल में क्या प्रभावित कर रहा है? या फिर वह किसी सनसनीखेज समाचार पर भावनात्मक प्रतिक्रिया करता है?

सबसे जरूरी है अर्थव्यवस्था को फिर उठाना। क्या हम उस पर फोकस कर रहे हैं? या हमें एक ऐसे विज्ञापन पर गुस्सा होना चाहिए, जिसमें कोई अंतरधार्मिक जोड़ा दिखाया जाता है। आप आज के युवा हैं और आपको इन सवालों के जवाब तय करने हैं। आप खुद को, इस देश को वहां ले जाएं, जहां आप जाना चाहते हैं। भारत को गरीब और घमंडी बनाने का लक्ष्य न रखें। भारत और खुद को अमीर और सौम्य बनाने का लक्ष्य रखें। इस फालतू फोन से छुटकारा पाएं और दिमाग को उत्पादक और रचनात्मक चीजों में व्यस्त करें। देश को बनाने वाली पीढ़ी बनें। (generation that 4Ges India ahead)एक 4Gotten पीढ़ी की तरह खत्म न हों।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अंग्रेजी-हिंदी के विशिष्ट विषयों को हटाया, अब सामान्य किताबें लागू

भोपाल (शप्र)। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नवमीं से बारहवीं तक संचालित अंग्रेजी और हिन्दी भाषा की किताबों से विशिष्ट और सामान्य विषयों को हटा दिया गया है। अब इन विषयों की सिर्फ दो ही किताबें हिन्दी और अंग्रेजी होंगी। इनकी पुस्तकें भी एक ही होंगी। यह व्यवस्था 9वीं एवं 11वीं में इसी साल और दसवीं-बारहवीं में अगले वर्ष यानि सत्र 2021-22 से भाषा की किताबें बदलेंगी। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बीते सप्ताह आदेश जारी कर नवमीं-ग्यारहवीं एवं 12वीं में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट व सामान्य विषय को हटाते हुए नए एनसीईआरटी की किताबें लागू करने के आदेश जारी किए थे। साथ ही एक और पत्र जारी किया गया कि इसमें किस कक्षा कि किताबें कब से लागू की जाएगी। उसमें यह जानकारी दी गई, लेकिन यह जानकारी छात्र-छात्राओं तक नहीं पहुंच सकी। इस कारण विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो सिलेबस दिए गया है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी में विशिष्ट और सामान्य विषयों को शामिल किया गया है तथा 9वीं एवं 11वीं कक्षा में के सिलेबस से हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट व सामान्य विषय को हटाते हुए एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया गया है।

पांच साल पहले बनी थी योजना

स्कूल शिक्षा विभाग ने पांच साल पहले वर्ष-2016 में 9 से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने की योजना तैयार की थी। सबसे पहले 2019-20 में 11वीं कक्षा में इससे लागू किया गया। 11वीं कक्षा में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान की एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया गया। इसके बाद 2020-21 में इन विषयों को 12वीं कक्षा में भी लागू किया गया। इसी तरह सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा में अंग्रेजी और हिन्दी भाषा की विशिष्ट और सामान्य किताबों को 2020-21 तक चलने की अनुमति दी थी एवं 10वीं और 12वीं कक्षा में यह व्यवस्था 2021 एवं 22 तक लागू रहेगी।

हायर सेकेंडरी की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित

इधर माशिमं ने बुधवार को हायर सेकेंडरी के पूरक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें एक लाख से अधिक विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। मंडल सचिव के अनुसार यह परीक्षा पिछले माह आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल एक लाख 21 हजार 697 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। इनमें प्रथम श्रेणी में 13,277 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जबकि 52,579 द्वितीय और 12,566 परीक्षार्थियों ने तृतीय श्रेणी की पात्रता हासिल की है। मंडल का कहना है कि कुल एक लाख 21 हजार 475 विद्यार्थी का परीक्षा फल घोषित किया गया है। हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा में परीक्षार्थियों के उत्तर का प्रतिशत 64.51 है।

रिजल्ट देखने के लिए गूगल पर newsjobmp.com सर्च करके ओपन करें

शिक्षण संस्थानों-छात्रों में विवाद निपटाने को एक जैसी व्यवस्था बनाने की कवायद

सुप्रीम कोर्ट तय करेगा स्कूल-कॉलेजों पर उपभोक्ता कानून लागू होगा या नहीं

यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों की याचिका विचार के लिए मंजूर की गई

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

क्या शिक्षण संस्थान की सेवाओं में कमी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत केस दायर हो सकता है, इसके कानूनी परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तमिलनाडु की विनायक मिशन यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनु सोलंकी और अन्य छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था- 'इस विषय पर अदालत के अलग-अलग विचार हैं। जैसे- शिक्षण संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में होंगे या नहीं, इसलिए याचिका पर विचार जरूरी है।' कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ दायर इस याचिका पर छह सप्ताह में जवाब दे।

छात्रों का दावा- शैक्षणिक सत्र बर्बाद हुआ, इसलिए हर छात्र को 1.4 करोड़ मुआवजा दें

छात्रों ने कहा है कि संस्थान ने झूठे वादे कर दाखिले के लिए आकर्षित किया। बाद में पता चला कि डिग्रियां भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इसलिए सेवा में खामी, शैक्षणिक सत्र गंवाने और मानसिक प्रताड़ना के लिए हर छात्र को 1.4 करोड़ रु. मुआवजा दिया जाए।

यूनिवर्सिटी का तर्क- शिक्षा कोई वस्तु नहीं, न संस्थान किसी तरह की सेवा प्रदान करते हैं

विनायक मिशन यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा- शिक्षा कोई वस्तु नहीं है, न ही संस्थान किसी प्रकार की सेवा देते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ही अपने पहले के फैसलों में कह चुका है। इसलिए यह मामला उपभोक्ता फोरम में दायरे में नहीं आता। मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता।

भास्कर EXPLAINER

हेमंत गोयल, उपभोक्ता मामलों के वकील, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों की वजह से ही भ्रम की स्थिति, इसलिए नई व्यवस्था जरूरी

▪ शिक्षण संस्थान के खिलाफ छात्र या अभिभावक कहां शिकायत कर सकते हैं? क्या प्रावधान हैं?
हाईकोर्ट और उपभोक्ता फोरम, दोनों ही जगहों पर केस दायर किए जाते रहे हैं।

▪ ज्यादा केस कोर्ट पहुंचते हैं या उपभोक्ता फोरम में?
ऐसे 90% से ज्यादा केस हाईकोर्ट पहुंचते हैं। क्योंकि, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार व्यापक हैं। उपभोक्ता फोरम की शक्तियां सीमित हैं।

▪ कोर्ट जाएं या उपभोक्ता फोरम, कैसे तय होता है?
आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अमूमन उपभोक्ता फोरम में ही शिकायत करते हैं। हाईकोर्ट में केस दायर करना काफी महंगा है। उपभोक्ता फोरम में बिना वकील के शिकायत होती है। समय और पैसा, दोनों ही कम लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर गाजियाबाद के व्यक्ति को उपभोक्ता फोरम में केस करना है तो अपने शहर में कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट में केस करने के लिए उसे लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ता है।

▪ शिक्षण संस्थानों के खिलाफ शिकायत के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण कानून में क्या व्यवस्था है?
इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष, दोनों तरह के फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए अनुपमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बनाम गुलशन कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा कोई वस्तु नहीं है। इसलिए, संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नहीं लाया जा सकता। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने ही पी. श्रीनीवसुलु बनाम पीजे एलेक्जेंडर मामले में कहा था कि शिक्षण संस्थान उपभोक्ता संरक्षण कानून के अधीन आते हैं। ऐसे ही कई मामलों की वजह से भ्रम की स्थिति है। इसलिए अब नई व्यवस्था होना जरूरी है।

▪ शिक्षण संस्थानों के उपभोक्ता कानून के दायरे में आने से क्या बदलेगा और कैसे?
पहले उपभोक्ता फोरम की शक्तियां बढ़ानी होंगी। अभी फोरम आदेश का पालन नहीं होने पर गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। दूसरे क्षेत्र से संबंधित मामलों में आदेश का पालन नहीं होने पर फरियादी को हाईकोर्ट ही जाना पड़ता है।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम

केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ का बोनस

सिर्फ 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मियों को ही मिलेगा लाभ

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को उत्पादकता और गैर उत्पादकता लिंक्ड बोनस की मंजूरी दे दी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को दी। बोनस की एकमुश्त राशि दशहरा से पहले कर्मचारियों के खातों में भेजी जाएगी। इससे सरकार पर कुल 3,737 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। जावड़ेकर ने कहा कि मध्य वर्ग बोनस की इस राशि को खर्च करेगा तो अर्थव्यवस्था में डिमांड को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी त्योहारों के मौसम में खर्च करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। उनमें एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम शामिल है।

ऐसे समझें... किसे बोनस

17 लाख कर्मचारी : सरकार के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस प्रोडक्शंस, ईपीएफओ, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 17 लाख नॉन-गैजेटेड एम्प्लॉयज को 2,791 करोड़ रुपए का उत्पादकता लिंक्ड इंसेंटिव बोनस।

13 लाख कर्मचारी : केंद्र सरकार में काम करने वाले 13 लाख अन्य कर्मचारियों को 906 करोड़ रुपए का गैर उत्पादकता लिंक्ड बोनस।

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा

रेलवे के 11.58 लाख कर्मचारियों को 2019-20 के लिए 78 दिन का बोनस मिलेगा। हालांकि, कोरोना काल में जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा गया है, उसे देखते हुए अनुमान था कि शायद इस साल बोनस न मिले। इसे देखते हुए रेल कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर को चक्का जाम की चेतावनी दी थी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बोनस की ऊपरी सीमा 17,951 रुपए ही होगी। पिछले साल भी 78 दिन का ही बोनस मिला था और उसकी सीलिंग 17,951 रुपए ही तय की गई थी।

एएफआरसी ने की सुनवाई

नर्सिंग कॉलेजों ने की पांच फीसदी फीस बढ़ाने की मांग

भोपाल | प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) की बुधवार को नर्सिंग, तकनीकी कॉलेजों की सुनवाई में कॉलेज संचालकों ने नए शिक्षा सत्र के लिए 5 फीसदी या इससे अधिक शुल्क बढ़ाने की मांग की है। सुनवाई में 43 कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें कॉलेजों से संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के संबंध में दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नर्सिंग कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि कोरोना की वजह से बहुत से छात्रों ने सत्र में आधी-अधूरी फीस ही दी है। अनेक ऐसे छात्र हैं, जिन्होंने फीस का भुगतान ही नहीं किया। इस वजह से कोर्स का संचालन करने और अन्य प्रकार के स्थापना व्यय निकालने में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस वजह से नए शिक्षा सत्र में कम से कम 5 फीसदी तक या इससे अधिक फीस बढ़ाई जानी चाहिए। इधर, एएफआरसी के अधिकारियों ने बताया कि अभी कॉलेजों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। फैसला बाद में लिया जाएगा।

एमपी बोर्ड ने जारी किए निर्देश, 9वीं, 11वीं में इसी साल बदलेंगे भाषा के विषय

10वीं और 12वीं में इस साल भी रहेंगे भाषा के 'विशिष्ट' और सामान्य विषय, अगले साल से बदलेगी व्यवस्था

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

एमपी बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन द्वारा संचालित 9वीं से 12वीं तक संचालित अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के विशिष्ट और सामान्य विषयों को हटा दिया गया है। अब सिर्फ दो ही किताबें हिन्दी और अंग्रेजी होंगी। इनकी किताबें भी एक ही होंगी। यह व्यवस्था 9वीं एवं 11वीं में इसी साल और बोर्ड की कक्षाओं 10वीं एवं 12वीं में अगले वर्ष यानी सत्र 2021-22 से लागू की जाएगी।

दरअसल एमपी बोर्ड ने बुधवार को एक आदेश जारी कर 9वीं, 11वीं एवं 12वीं में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट व सामान्य विषय को हटाते हुए नए एनसीईआरटी की किताबें लागू

करने के आदेश जारी किए थे। साथ ही एक और भी लेटर जारी किया गया। इसमें किस कक्षा कि किताबें कब से लागू की जानी है, उसमें यह जानकारी दी गई, लेकिन यह जानकारी छात्र-छात्राओं तक नहीं पहुंच सकी है। इस कारण विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो सिलेबस दिए गया है, उसमें हिन्दी और अंग्रेजी में विशिष्ट और सामान्य विषयों को शामिल किया गया है तथा 9वीं एवं 11वीं कक्षा में के सिलेबस से हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट व सामान्य विषय को हटाते हुए एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया गया है। अभी तक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी विशिष्ट अंग्रेजी और सामान्य हिंदी विषय को लेकर पढ़ाई करते थे।

कॉमर्स व आर्ट्स में एक जैसा होगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट

हायर सेकंडरी (12वीं) में कॉमर्स व आर्ट्स पढ़ने वाले के लिए इकोनॉमिक्स सीबीएसई के अनुसार समान कोर्स लागू किया गया है। अतः इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कोर्स कॉमर्स व आर्ट संकाय में एक समान रहेगा।

पहले बनी थी योजना

स्कूल शिक्षा विभाग ने पांच साल पहले वर्ष-2016 में 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की योजना तैयार की थी। सबसे पहले 2019-20 में 11वीं में इससे लागू किया गया। 11वीं में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान की एनसीईआरटी की किताबें शामिल की गईं। इसके बाद 2020-21 में इन विषयों को 12वीं में भी लागू किया गया। सरकार ने 9वीं और 11वीं में अंग्रेजी और हिन्दी भाषा की विशिष्ट और सामान्य किताबों को 2020-21 तक चलाने की अनुमति दी थी। 10वीं और 12वीं में यह व्यवस्था 2021 एवं 22 तक लागू रहेगी।

15 लाख विद्यार्थियों के लिए महज 10 लाख रु. का प्रावधान

आदिवासी छात्रों की गंभीर बीमारी पर प्रति छात्र एक रुपए भी खर्च नहीं

सीताराम ठाकुर • भोपाल

पीपुल्स समाचार स्पेशल

प्रदेश में आदिवासी कल्याण के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। कहने को तो बजट में इनके लिए 21 प्रतिशत प्रावधान है, परन्तु आदिवासी छात्र-छात्राओं के कल्याण में भी भेदभाव सामने आया है। करीब 15 लाख छात्र-छात्राओं की गंभीर बीमारी और मौत पर सरकार ने 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यानि एक छात्र पर एक रुपए भी खर्च नहीं किए जा रहे हैं। कही ये कटौती कोरोना महामारी के कारण तो नहीं की गई है।

आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए वित्त विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए जो बजट जारी किया है, उसमें 6 हजार 628 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन इसमें से अधिकांश राशि विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाएगी। खासकर आश्रमों में 68 हजार छात्र-छात्राओं की व्यवस्था के लिए 164.46 करोड़, हाई एवं हायरसेकेंडरी स्कूलों के लिए 672 करोड़, माशिमं को शुल्क पूर्ति के लिए 10 करोड़, स्पेशल एंड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी के लिए 187.28 करोड़, सीनियर छात्रावासों के लिए 168.37 करोड़, जिला प्रशासन के लिए 100 करोड़, परियोजना मुख्यालय के लिए 22.55 करोड़, प्राथमिक शालाओं के लिए 2822 करोड़ तथा माध्यमिक शालाओं के लिए 1665.62 करोड़, जनजाति बस्तियों के विकास के लिए 50 करोड़ तथा माडा पॉकेट क्लस्टर के विकास के लिए 28.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर राशि का प्रावधान

सरकार ने बजट में मात्र 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग स्कूल, छात्रावास तथा आश्रम आदि में यदि किसी छात्र को गंभीर बीमारी हो जाती है अथवा किन्हीं कारणों से उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने यह राशि रखी गई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यानी किसी बड़ी दुर्घटना, घटना में छात्रों की मौत होने पर भी इतनी कम राशि से कैसे मदद की जा सकेगी, जब छात्र-छात्राओं की संख्या 15 लाख हो।

स्कूलों में छात्रों की स्थिति

स्कूल	संख्या	छात्र-छात्राएं
प्राथमिक	12643	613950
माध्यमिक	4369	333269
हाईस्कूल	804	179747
हायर सेकंडरी	786	82970
आश्रमशालाएं	1083	68000
आवासीय संस्थाओं में		170000

स्रोत : आदिम जाति कल्याण विभाग

बीमार होने पर खर्च होगी राशि मुआवजे का भी है प्रावधान

जिलों में किसी आदिवासी छात्र-छात्रा के गंभीर रूप से बीमार होने अथवा किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए 10 लाख रुपए की राशि का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है।

– पल्लवी जैन गोविल,
प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण

आईटीआई में लिया 29 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रवेश

भोपाल, (प्रसं)। मध्यप्रदेश के शासकीय आईटीआई संस्थानों में अब तक कुल 29,546 बच्चों ने विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश लिया है। इसमें सीटीएस में 28,558, आईएमसी में 547 तथा डीएसटी में 441 प्रवेश दर्ज किए गए हैं।

आज शाम चार बजे जारी होगी अभ्यार्थियों की मेरिट सूची

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मप्र राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा ने बताया कि पूर्व में रजिस्टर्ड आवेदक चाहे तो अपने रजिस्ट्रेशन तथा च्वाइस फिलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार, 22 अक्टूबर को एमपी ऑनलाइन द्वारा शाम चार बजे पोर्टल पर अभ्यार्थियों को मेरिट सूची जारी की जाएगी। मैरिट सूची के अनुरूप अभ्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण शुल्क भी रात्रि 12 बजे के पूर्व जमा करवाया जाएगा।

23 अक्टूबर को रिक्त सीटों की जानकारी तथा आईटीआई द्वारा वेटिंग सूची अनुसार अभ्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच एवं प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने की कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा ने एमपी ऑनलाइन को सीएलसी राउंड के लिए रजिस्टर्ड एवं ऐसे अभ्यार्थी जिनका प्रवेश सीएलसी राउंड तक नहीं हुआ है, उन्हें 22 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैसेज करने के निर्देश दिए है।

प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्रीय मूल्य सूचकांक का अंतर समान होने की उम्मीद जागी

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर्मचारियों के हितों में की गई घोषणा को लेकर सरकारी तंत्र में आशाओं की एक नई किरण जागी है। लोक सेवकों का कहना है कि कोरोना संकट का बज्र खेलती राज्य सरकार की जैसे ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी वैसे भी उनके प्रासंगिक लाभों का भी भुगतान होगा। ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि हमें पूरा भरोसा है। प्रदेश में कर्मचारियों के अनुसार राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त का 25 फीसदी देने की भी घोषणा की है। इसका फायदा सरकारी विभागों और निगम मंडलों के करीब 7 से 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इससे सरकार पर 375 करोड़ का भार आएगा। सरकार को एरियर्स की किस्त इस साल मई 2020 में देनी थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त की शेष राशि भी वित्तीय वर्ष में भी मिल जाएगी। बकाया महंगाई भत्ता व इंक्रीमेंट की एक-एक पाई कर्मचारियों को मिलेगी। कर्मचारियों का तर्क है कि केंद्र सरकार अपने केंद्रीय सेवकों को दिवाली हैप्पी करने की तैयारी में है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को सप्तम वेतनमान में 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन का तोहफा देते हुए उनके लिए फेस्टिवल एडवांस स्कीम लांच की है। इसके तहत 3 करोड़ औद्योगिक मजदूरों को भी इजाफा हो सकता है। मूल्य सूचकांक के बेस ईयर में बदलाव होने से भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा । 48 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों पेंशनर्स को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा।

सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों को सुविधाएं दे सकती है सरकार: तिवारी

वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी कहते हैं कि सरकार को केंद्रीय मूल्य सूचकांक से बने अंतर को पटना होगा। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार सूचकांक के आधार पर उसका कैलकुलेशन कर अपने कर्मचारियों को सुविधाएं दे सकती है। तो फिर मध्यप्रदेश में भी रोकी गई सुविधाओं का भुगतान करने का सरकार रास्ता निकालेगी। ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया था। तब 18 माह का एरियर तीन किस्तों में देने का निर्णय हुआ था। दो किश्ते दी जा चुकी है। तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान मई 2020 में होना था। केंद्र ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया था। इस 5 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते से करीब 1400 करोड़ का भुगतान राज्य में अप्रैल के वेतन से जोड़कर किया जाना था लेकिन कोरोना संकट के कारण सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। अब 14 सौ करोड रुपए का वह 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को देना शेष है।

मुख्यमंत्री को करना होगी लगातार समीक्षा: विजय शंकर

अजाक्स के प्रवक्ता विजय शंकर श्रवण का कहना है कि दिवाली के पहले मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को दी गई सौगात बड़ी ताकत का कार्य करेगी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संकटकाल की विषम परिस्थितियों में कर्मचारियों का ख्याल रखा। यह काम वाकई में सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा का समय से पालन हो। इसके लिए समीक्षा जरूरी है। ताकि अफसरशाही कर्मचारियों के मिलने वाले लाभ में कहीं रोड़ा न बन सके। इस दिशा में मुख्यमंत्री को स्वयं नजर रखनी होगी।

त्योहार के बीच घोषणा से पूरे कर्मचारी जगत में उत्साह: दिलीप इंगले

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप इंगले का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा से पूरे प्रदेश के कर्मचारी जगत में उत्साह है। इनका कहना है कि इस समय यह लाभ मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। कर्मचारी त्योहार आसानी से मना सकेंगे। कर्मचारियों के बीच जो संशय की स्थिति बैठी हुई थी। वह भी दूर होगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र के समान जो डीए मिलना बकाया है उसका भुगतान भी राज्य सरकार समय से करें तो कर्मचारियों के परिवारों में एक नया उत्साह पैदा होगा।

सरकारी आईटीआई में 29,456 स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन

भोपाल। सरकारी आईटीआई संस्थानों में अब तक कुल 29 हजार 546 बच्चों ने विभिन्न ट्रेड्स में एडमिशन लिया है। इसमें सीटीएस में 28 हजार 558, आईएमसी में 547 तथा डीएसटी में 441 प्रवेश दर्ज किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड षणमुख प्रिया मिश्रा ने बताया कि पूर्व में रजिस्टर्ड आवेदक चाहे तो अपने रजिस्ट्रेशन तथा चॉइस फिलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर को एमपी ऑनलाइन द्वारा शाम 4 बजे पोर्टल पर अभ्यार्थियों को मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची के अनुरूप अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण शुल्क भी रात्रि 12 बजे के पूर्व जमा करवाया जाएगा। 23 अक्टूबर को रिक्त सीटों की जानकारी तथा आईटीआई द्वारा वेटिंग लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच एवं प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने की कार्यवाही की जाएगी। षणमुख प्रिया मिश्रा ने एमपी ऑनलाइन को सीएलसी राउंड के लिए रजिस्टर्ड एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सीएलसी राउंड तक नहीं हुआ है, उन्हें 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैसेज करने के निर्देश दिए हैं।

स्टेट की नौकरी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से लाखों उड़ाए!

डीईओ ने लिखा सीजीएचएस को पत्र

नगर प्रतिनिधि | जबलपुर बच्चों को अच्छाई और बुराई का फर्क बताने वाली शिक्षिका न जाने खुद यह फर्क करना कैसे भूल गईं? दरअसल, माध्यमिक स्कूल गोकलपुर की टीचर होते हुए शिक्षिका प्रतिभा दुबे ने सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी ली। जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों की सेवाओं का फायदा उठाया और भुगतान करना पड़ा केंद्र सरकार को। अब मामले का खुलासा होने पर जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने सीजीएचएस के एडीशनल डायरेक्टर को पत्र लिखते हुए कार्यवाही की बात कही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम की समन्वय समिति ने ऐसे मामले पर छानबीन शुरू कर दी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी द्वारा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लिया गया। गोकलपुर की शिक्षिका के पिता केंद्रीय कर्मचारी थे लिहाजा, परिजनों को भी सीजीएचएस की सुविधा हासिल हो सकती है, लेकिन एक सीमा तक। समिति के सदस्यों का कहना है कि अविवाहित पुत्री अथवा उसके शादी के बाद विधवा हो जाने पर भी दोबारा सीजीएचएस का लाभ हासिल हो सकता है बशर्ते उसकी आय 9 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, डीईओ की चिट्ठी के बाद सीजीएचएस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पी-4

राज्य सरकार की शिक्षिका को सीजीएचएस की सुविधा का प्रावधान ही नहीं है। भले ही उनके परिजन केंद्रीय कर्मचारी रहे हों। डीईओ का पत्र मिलने के बाद इस मामले की जाँच की जा रही है। निष्कर्ष आने के बाद रिकवरी की कार्यवाही भी मुमकिन है।

-राजेंद्र रावत, एडीशनल डायरेक्टर, सीजीएचएस

मैंने राज्य सरकार को शपथपत्र दिया कि मुझे स्टेट की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा नहीं चाहिए। लिहाजा, इस आधार पर ही सीजीएचएस कार्ड बनवाया गया है।

बैस्ट एनसीसी कैडेट बनने दी परीक्षा

जबलपुर। कैडेट वेलफेयर सोसायटी के अंतर्गत ग्रुप लेवल बैस्ट कैडेट चयन प्रक्रिया का आयोजन हुआ। जिसमें जबलवुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर छिकारा का निर्देशन रहा। चयन प्रक्रिया 4 एमपीसीटीआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नितिन सिनागरे, 2 एमपी नेवल के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर अमित शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में पूरी हुई। द्वि-दिवसीय चयन प्रक्रिया में जबलपुर ग्रुप के अंतर्गत सभी यूनिट्स से संबंधित महाविद्यालयों एवं विद्यालयों से चयनित उत्कृष्ट एनसीसी कैडेट्स की लिखित परीक्षा हुई। इसके साथ ही साक्षात्कार, फायरिंग परीक्षण एवं ड्रिल टेस्ट भी हुआ। संचालन में नायब सूबेदार पीएम मालीवाड़, एचएमटी मुकेश कुमार एवं हवलदार सुरेन्द्र कुमार पांडेय का योगदान रहा।पी-3

बागवान अनुभव, प्यार, संस्कार सब इनसे जुड़ा। जीवन भर की पूँजी इनके लिए परिवार ही तो है, तपती धूप हो सर्दी या बरसात। कभी थमे नहीं। परिवार की खुशियाँ ही इन्हें खुशी देती। भावी पीढ़ी के यह सच्चे मार्गदर्शक हैं। इस कॉलम के माध्यम से दैनिक भास्कर ने शहर के बुजुर्गों से जीवन जीने की कला के बारे में जानने की कोशिश की है।

मुस्कुराकर करें परीक्षाओं का सामना

हमारा परिवार **पत्नी** - सुमन अग्रवाल। **बेटे-बहुएँ** - डॉ. देवेन्द्र-नेहा व वीरेन्द्र-पेम। **बेटी-दामाद** - रेखा-सतीश कुमार अग्रवाल। **पोता-पोती** - अंचित व अंश। **नाती** - हर्ष-ताहिना व यश।

अधारताल निवासी 84 वर्षीय डॉ. आरके अग्रवाल का मानना है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखें

सिटी रिपोर्टर, जबलपुर। कितना भी कठिन समय आए, ईश्वर पर भरोसा रखें। सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ऐसे ही विचार अधारताल निवासी 84 वर्षीय डॉ. आरके अग्रवाल ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि जीवन में परीक्षाएँ तो देनी ही पड़ती हैं। मुस्कुराकर परीक्षा देने से परिणाम अच्छे मिलते हैं।

अविस्मरणीय पल | इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में मेरा एडमीशन हुआ, तब मैं बहुत खुश था।

● आपकी जिन्दगी का सबसे महत्वपूर्ण वह कौन-सा पल था, जिसमें आपने सफलता पाई और वह किस तरह आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकता है?

मैं दो वर्ष का था, जब माँ का साथ छूट गया। पिता जी ने मेरी परवरिश की। उन्होंने मेरी पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। मैंने नागपुर और दिल्ली से अपनी शिक्षा पूरी की। एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। सन् 1995 में सेवानिवृत्त हुआ। विद्यार्थियों और अपने बच्चों में कभी भेद भाव नहीं किया। आज मेरे पढ़ाए छात्र अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। कहीं भी मिलते हैं तो मेरा आदर सम्मान करते हैं। जीवन में सभी से मिलने वाला सम्मान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, जिससे परिवार, समाज और देश का विकास हो।

● आपने जो अपनी विरासत संजोई है और जिंदगी में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, वे किस तरह भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं?

ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा मेरी विरासत है क्योंकि मेरी शिक्षा पर पिता जी ने शुरूआत से ही ध्यान दिया। इसी तरह मैंने भी अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दिलाई। मेरे तीनों बच्चे एजुकेटेड हैं। इसके साथ ही उन्हें ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने की सीख भी दी।

● अपने शहर, समाज और देश के लिए अब क्या करना चाहते हैं और यह भी बताइए कि आज की पीढ़ी को क्या करने की जरूरत है?

मेरा युवाओं को यही संदेश है कि किसी भी काम को छोटा-बड़ा न समझें। मेहनत से काम करें, ईमानदारी रखें। पढ़ाई पर ध्यान दें। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। घर को व्यवस्थित रखने की आदत डालें।पी-3

नोट : साथ बिताए गए यादगार पलों की फोटो फैमिली मेम्बर्स ने खींचा की है।

एनटीए ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप को गलत बताया

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 16 अक्टूबर को नीट का परिणाम घोषित किया था। इसके बाद एक अभ्यर्थी ने रिजल्ट में गड़बड़ी होने और शिकायत के बाद उसे ठीक किए जाने का आरोप लगाया। अब एनटीए ने इन आरोपों पर आधिकारिक जवाब देते हुए गलत परिणामों के दावों को पूरी तरह से नकार दिया है। एक अभ्यर्थी ने दावा किया था कि उसके 650 अंक हैं जबकि परिणाम में 329 अंक ही दिए गए हैं। आपत्ति जताने पर उसके अंक ठीक कर दिए गए।

एमपी बोर्ड हायर सेकेण्डरी पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित

संवाददाता, जबलपुर। माशिमं द्वारा इस साल ली गई हायर सेकेण्डरी पूरक परीक्षा के रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में कुल 121697 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से प्रथम श्रेणी में 13227, द्वितीय श्रेणी में 52579 और तृतीय श्रेणी में 12566 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सभी छात्र अपना रिजल्ट माशिमं की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

9वीं-11वीं से हटाई गई विशिष्ट व सामान्य भाषाएँ • माशिमं ने वर्ष 2020-21 के सत्र से हाई और हायर सेकेण्डरी की कक्षाओं से विशिष्ट और सामान्य भाषा का प्रावधान हटा दिया है। यानी अब 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में विशिष्ट और सामान्य भाषा के दो पाठ्यक्रम व प्रश्नपत्रों के बजाय एक ही भाषा का प्रावधान रहेगा। इसी तरह हायर सेकेण्डरी के वाणिज्य और कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय के लिए सीबीएसई के अनुसार समान पाठ्यक्रम और पुस्तकें लागू की गई हैं।

एनसीटीआई और बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद

M.P. Higher Edu. Department

भोपाल। एनसीटीआई और बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी धीरेंद्र शुक्ला का कहना है कि एनसीटीआई कोर्स सहित बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया का अंतिम चरण भी खत्म हो गया है। करीब 22 हजार से ज्यादा सीटें इस दौरान भरी थीं।

अलग-अलग कोचिंग के विज्ञापनों में एक ही टॉपर्स की फोटो देख भड़के अभिभावक

टॉपर्स को अपना बताने वाली कोचिंग से दूसरे छात्रों के पेरेंट्स ने फीस वापस मांगी

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

लाखों रुपए फीस वसूलने और छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोचिंग्स संस्थानों द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। टॉपर्स छात्रों को दोनों कोचिंग अपना स्टूडेंट बता रहे हैं। एलेन और आकाश कोचिंग के इस फर्जीवाड़े को प्रदेश टुडे ने कल 20 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित किया था। इसके बाद कई परेंट्स ने अपने बच्चों के एडमिशन निरस्त करने और फीस वापस मांगी है।

आप भी पूछें सवाल...

एलेन के संचालक गोविंद अग्रवाल (9414183919) और आकाश कोचिंग के वीपी अनुराग जगाती (9871226677) से आप भी सवाल पूछें कि आखिर यह फर्जीवाड़ा क्यों ?

अभिभावक बोले... झूठी पब्लिसिटी कर रहे कोचिंग्स

यह पहला विज्ञापन एलेन का है और दूसरा आकाश कोचिंग का है,इसमें इन दोनों कोचिंग ने टॉपर्स को अपना स्टूडेंट बताया है।

लाखों रुपए लेकर छात्रों को नीट, जेईई, सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर्स का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दूसरे छात्रों के परिजन आक्रोशित हैं। मंगलवार को प्रदेश टुडे में कोचिंग सेंटर्स के फर्जीवाड़े की खबर प्रकाशित होने के बाद कई अभिभावक आकाश और एलेन कोचिंग सेंटर्स के ऑफिस पहुंचे और फीस वापसी की मांग करने लगे। अभिभावकों का कहना था कि सिर्फ अपनी कोचिंग का नाम करने के चक्कर में कोचिंग सेंटर टॉपर्स का फोटो छापकर झूठी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बच्चे यदि यहां पढ़े तो उनका भविष्य खराब हो सकता है।

प्रदेश टुडे फर्जीवाड़ा

सोशल मीडिया पर कोचिंग सेंटर्स के एड वायरल, यूजर्स उठा रहे सवाल

नीट यूजी 2020 की परीक्षा में टॉप आए छात्रों की फोटो लगे विज्ञापन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इन एड में कई छात्र ऐसे है जिनको दोनों कोचिंग संस्थानों ने अपना छात्र बताया है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स कोचिंग सेंटर्स के इन कारनामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश टुडे ने नाम कमाने के चक्कर में टॉपर्स को अपने संस्थान का छात्र बताने वाली कोचिंग का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। इसको लेकर अब अभिभावक इन संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों की फीस वापस करने की मांग कर रहे हैं।

पाठ्यक्रम को लेकर डाइट प्राचार्यों से सुझाव मांगे

ग्वालियर। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार से अनुमोदन के बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 60% विषयवस्तु को फेस टू फेस मोड में और 40% विषय वस्तु को होम असाइनमेंट व प्रोजेक्ट कार्य के रूप में पूर्वनियोजित किया गया है। कक्षा 1 से 8वीं के पूर्वनियोजित पाठ्यक्रम को पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम की योजना पर समीक्षा होनी है। जिसमें चार बिंदुओं पर फीडबैक मांगा गया है। लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति कैसे और इसमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करने में छात्रों की समझ कैसे बनेगी और क्या इस तरह की व्यवस्था शिक्षकों पर शिक्षण के दबाव को कम कर सकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने डाइट प्राचार्यों से 30 अक्टूबर तक फीडबैक मांगा है।

अंकों के आधार पर मिलेगा एमबीए-एमसीए में प्रवेश

ग्वालियर। बीई, बी-फॉर्मेसी, एमई एमटेक सहित विभिन्न तकनीकी कोर्सेस के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। अब जल्द ही एमबीए और एमसीए के लिए भी ऑनलाइन काउंसिलिंग शुरू करेगा।

प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग होगी

राज्य शासन ने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आने के कारण फर्स्ट व सेकंड ईयर के औसत अंक के आधार पर एडमिशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर से एमबीए और एमसी, दोनों कोर्सेस में एक साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण से हुई देरी के कारण अब इन दोनों कोर्स के लिए सिर्फ एक राउंड में एडमिशन प्रक्रिया होगी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने यूपी फाइनल ईयर के रिजल्ट घोषित कर दिए है लेकिन सितंबर तक अन्य विश्वविद्यालयों के रिजल्ट अटके हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आधार पर एडमिशन मिलेगा।

स्नातक की सीट अलॉट, 26 तक जमा करनी होगी फीस

ग्वालियर। सोमवार को तीसरे चरण की कॉलेज लेवल काउंसिलिंग की सीटों का अलोटमेंट कर दिया गया। विद्यार्थियों को 26 अक्टूबर तक फीस जमा करनी होगी। वहीं दूसरी ओर स्नातकोत्तर के सीएलसी राउंड के पंजीयन की भी आखिरी तारीख थी। 24 अक्टूबर के बीच सीट अलोटमेंट होगा। ज्ञात हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने 15 से 30 फीसद सीटें बढ़ाने के निर्देश दिए थे। सीएलसी राउंड के लिए कॉलेजों ने सीटें बढ़ा ली थीं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए। स्नातक की सीटें ऑलोट कर दी हैं।

एमएलबी कॉलेज में बीए में 256, बीकॉम 186, बीकॉम कंप्यूटर में 27 व बीबीए में 26 सीटें अलोट की हैं। केआरजी में बीए में 458, बीकॉम में 176, बीबीए में 16 सीटें अलोट की हैं। साइंस कॉलेज में बीएससी मैथ ग्रुप में 264 व बायोग्रुप में 176 सीटें अलोट की गई हैं। इन विद्यार्थियों को 26 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करनी होगी। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते विभाग ने फीस जमा करने में राहत दी है। 50 फीसद फीस पहले जमा करनी है, उसके बाद दो स्टॉलमेंट में फीस जमा कर सकते हैं।

विक्रांत कॉलेज के 11 छात्र-छात्राएं गुजरात की प्रतिष्ठित नेशनल कंपनी में चयनित

ग्वालियर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स द्वारा अपने बी.टेक. (मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रीकल एवं पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा) के छात्र/छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लोज कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कंपनी कैस्पियन इंडिया इंजनकॉन प्रा.लि. को संस्थान द्वारा आमंत्रित किया गया। सी.आई.ई. प्रा. लि. कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रकांत मिश्रा एवं एचआर प्रेरणा मिश्रा के मार्गदर्शन में ऑनलाइन प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी की गई। कैंपस इंटरव्यू की पूरी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, टैक्निकल इंटरव्यू एवं एच.आर. इंटरव्यू के अन्तर्गत की गई। राष्ट्रीय कंपनी के दोनों पदाधिकारियों के द्वारा चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले 06 पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एवं 05 बी.टेक. के छात्रों का चयन अच्छे वार्षिक पैकेज पर किया गया।

विक्रांत समूह के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी प्रो रोहित गुप्ता ने बताया कि इसी माह के अंत तक बी.टेक., पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एवं एमबीए के छात्रों के लिए तीन नेशनल एवं मल्टीनेशनल कंपनियों को कैंपस इंटरव्यू के लिए संस्थान द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। ऑनलाइन क्लोज कैंपस ड्राइव के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी में चयनित हुये सभी छात्रों को विक्रांत समूह के चेयरमैन आरएस राठौर, सचिव विक्रांत सिंह राठौर, डीएमडी श्रीमती जगविंदर कौर, ग्रुप डायरेक्टर डॉ. सत्यनारायण, डायरेक्टर डॉ. संजय सिंह कुशवाह, प्रभारी प्राचार्य प्रो. आनंद बिसेन, समस्त प्राध्यापकों एवं सहपाठियों ने बधाई दी।

Vikrant
GROUP OF INSTITUTIONS

10वीं और 12वीं में नहीं होगी सामान्य एवं विशिष्ट भाषा

भोपाल ■ प्रशासनिक संवाददाता

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं में सामान्य एवं विशिष्ट भाषा संबंधी विषयों पर कैंची चलाई गई है। मंडल का कहना है कि विद्यार्थी अब एक ही प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे।

एक ही प्रश्न-पत्र की परीक्षा देंगे विद्यार्थी

इधर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी एसके चौरसिया ने बताया कि हाईस्कूल और हाई सेकंडरी परीक्षाओं में वर्ष 2021-22 से विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया है कि मंडल द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में वर्ष 2020-21 से कक्षा नवीं एवं 11वीं कक्षाओं में अब विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान नहीं होगा। इसके स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अंतर्गत विशिष्ट एवं सामान्य भाषा के अलग-अलग पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र ना होकर केवल एक भाषा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदी विशिष्ट भाषा एवं सामान्य के स्थान पर हिंदी भाषा होगी। अंग्रेजी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा होगी। संस्कृत एवं उर्दू विशिष्ट के स्थान पर संस्कृत और उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले सत्र में मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली हायर सेकेंडरी में हाई स्कूल की परीक्षाओं में भी आप विशिष्ट भाषाएं एवं सामान्य भाषा के स्थान पर संबंधित विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा।

घर बैठे ओलिंपियाड की परीक्षा देंगे छात्र

भोपाल। स्कूली छात्रों के लिए ओलंपियाड परीक्षाओं के सबसे बड़े आयोजक साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एसओएफ ने घोषणा की है कि ओलंपियाड परीक्षाएं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को सर्वोपरि मानते हुए सभी छात्र अपने घरों से एसओएफओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हो सकेंगे। हर साल भारत और अन्य देशों के लाखों छात्र एसओएफओलंपियाड परीक्षाओं में शामिल होते हैं। एसओएफ के संस्थापक निदेशक महाबीर सिंह ने कहा कि एसओएफइस साल चार ओलंपियाड परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें एसओएफइंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड, एसओएफइंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, एसओएफनेशनल साइंस ओलंपियाड और एसओएफ इंटरनेशनल गणित ओलंपियाड शामिल हैं। पंजीकरण खुले हैं और छात्र प्रत्येक तिथि से 15 दिन पहले तक एसओएफकी वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। परीक्षाएं नवंबर से शुरू हो जाएंगी।

पालक महासंघ का आरोप निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी जारी

स्कूल रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बहाने फीस वसूली के लिए बना रहे अभिभावकों और बच्चों पर दबाव, बच्चे के मोबाइल पर भेज रहे मैसेज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

फीस वसूली का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच कुछ निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। निजी स्कूल अब फीस वसूलने को लेकर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। पालक महासंघ मप्र का आरोप है कि निजी स्कूल रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बहाने फीस वसूली के लिए अभिभावकों और बच्चों पर दबाव बना रहे हैं।

पालक महासंघ मप्र के महासचिव प्रबोध पंढ्या ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड के निर्देशानुसार कक्षा 9 और 11 में बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसकी अंतिम तिथि बोर्ड द्वारा 4 नवंबर है। वहीं कक्षा 10 और 12वीं के एग्जाम फार्म भराए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। साथ ही प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी जानकारी मांगी गई है।

इधर, निजी स्कूलों की घोषणा के बाद महासंघ मैदान में

2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल्स द्वारा शिक्षा-शिक्षक बचाओ सत्याग्रह प्रदर्शन की घोषणा के बाद अब पालक महासंघ मप्र भी मैदान में आ गया है। पालक महासंघ मप्र के महासचिव प्रबोध पंढ्या ने एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल्स द्वारा पालक संघों पर की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि अगर स्कूलों द्वारा पालकों की मांगों का समर्थन नहीं किया जाएगा तो पालक महासंघ पूरे राज्य में विरोध करेगा। पालक महासंघ जल्द इसको लेकर सरकार को ज्ञापन देगा। साथ ही कि प्राइवेट स्कूलों का यह सत्याग्रह प्रदेश के सभी शहरों में एक साथ किया जाएगा।

फीस वसूली का तरीका

महासचिव पंढ्या ने बताया कि स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है, स्कूलों द्वारा केवल उन्हीं बच्चों को परीक्षा की अनुमति दी जा रही है, जिन्होंने पूरी ट्यूशन फीस जमा कर दी है, जबकि ऑनलाइन क्लास के लिए इस तरह की परीक्षा के समय में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। पंढ्या ने कहा है कि बच्चों द्वारा टीसी मांगने पर फीस मांगी जा रही है। फीस जमा नहीं करने पर टीसी देने से मना किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास में भी सभी सेशन के बच्चों को एक साथ बैठाकर एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है।

क्या कहते हैं अभिभावक

बच्चों पर बना रहे दबाव

स्कूलों द्वारा बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है कि पहले फीस जमा करवाओ उसके बाद ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमने स्कूल की इस मनमानी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सहित कलेक्टर को आवेदन दिया है।

शिव शर्मा, अभिभावक

मैसेज भेजने से बच्चे परेशान

स्कूलों द्वारा लगातार फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। बच्चों के मोबाइल फोन पर ऑनलाइन क्लास ली जा रही है स्कूल उसी मोबाइल पर फीस को लेकर मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे में बच्चे परेशान हो रहे हैं।

पंडित संजीव शर्मा, अभिभावक

पालक संघों पर की गई टिप्पणी निराधार

परिपत्र जिसमें कहा गया है कि पालक संघ पर दबाव बनाते हैं, लेकिन यह सरासर बच्चों की फीस माफ कराने का है।

कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष पालक महासंघ, मप्र

आयोग के हस्तक्षेप के बाद छात्राओं को मिली टीसी, डीईओ ने भेजा प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद दो छात्राओं को संबंधित स्कूलों द्वारा टीसी जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ने आयोग को इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है। मामला वर्ष 2019 का है। आयोग में दर्ज प्रकरण के अनुसार आईशीलो कॉन्वेंटी, कोलार निवासी आवेदक ने आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर किमाबाद स्कूल कोलार रोड द्वारा उनकी बेटियों और रोकने तक में पढ़ रही दोनों बेटियों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण उनकी बेटियों के स्कूल नहीं जाने की शिकायत कर इस संबंध का निराकरण कराने का अनुरोध किया था। आयोग द्वारा मामले में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से रिपोर्ट मांगकर निरंतर सुनवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि आवेदक की पुत्रियों की टीसी जारी कर दी गई है। अतिम निराकरण पश्चात अब यह प्रकरण आयोग में नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर उठाए सवाल, कई बिंदुओं पर हुई चर्चा

3 साल से आरटीई की राशि नहीं, कैसे संचालित हों स्कूल

स्टार समाचार | सतना

सरकार ने मुफ्त शिक्षा के नाम पर वोट तो कबाड़ लिए लेकिन अब आरटीई की राशि प्राइवेट स्कूलों को देना भूल गई है नतीजतन कोविडकाल में आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रहे सकूल प्रबंधनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने जिले के 90 फीसदी विद्यालय प्रबंधनों को वर्ष 2017 से तो 40 फीसदी विद्यालय प्रबंधनों को बीते 5 -6 सालो सें आरटीई की राशि नहीं दी है । नतीजतन कोरोनाकाल में कई स्कूल प्रबंधनों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें स्कूल का मेंटेनेंस व स्टाफ का वेतन जुटाने तक में दिक्कतें हो रही हैं। सरकार ने

कोरोनाकाल में प्रभावित कई सेक्टर्स को मदद पहुंचाई है लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को किसी भी प्रकार की राहत देने का प्रयास नहीं किया जिससे निजी शैक्षणिक संस्थानों की माली हालत लड़खड़ाती जा रही है। मंगलवार को सरकार का ध्यान निजी स्कूल संचालकों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने के उद्देश्य से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक प्रभात विहार कालोनी स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में आयोजित हुई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा 22 अक्टूबर को भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम के रूपरेखा व रणनीति तैयार की गई।

पांच सूत्रीय बिंदुओं पर चर्चा

लिटिल फ्लावर स्कूल में आयोजित हुई बैठक में सतना के अलावा कोठी, अमरपाटन, जैतवारा, बिरसिंहपुर समेत समूचे जिले के निजी स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी पहुंचे जहां आरटीई का पैसा न मिलने की समस्या प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान मान्यता के लिए संबद्धता शुल्क , किरायानामा शुल्क, मान्यता शुल्क में राहत प्रदान करने के साथ ही मान्यता अवधि को पांच साल तक बढ़ाए जाने व मान्यता नियमों को कोविडकाल में सरल करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा विद्यालयों को खोलने, प्रापर्टी टैक्स, बिल व विभिन्न ऋणों की एमईआई में राहत देने की मांग भी प्रमुखता से उठी। बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोज दुबे, लिटिल फ्लावर स्कूल संचालक सिद्धार्थ पांडेय, आरएन त्रिपाठी, श्रवण तिवारी , आशुतोष पांडे , , रमेश निगम , विनोद अग्रवाल , राजेश नामदेव , हरिओम द्विवेदी , पुष्पेंद्र सिंह , दीपक शुक्ला समेत 30 विद्यालय संचालक मौजूद रहे।

शिक्षा अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

निःशुल्क वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि पोर्टल पर सुनिश्चित करें : कियावत

स्टार समाचार | भोपाल

पाठ्य पुस्तक निगम एवं गत वर्ष की शेष पुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण विद्यार्थियों को कर प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर सात दिवस में अनिवार्य रूप करना सुनिश्चत करें। उक्ताशय के निर्देश संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने बुधवार को संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में भोपाल, विदिशा और सीहोर के जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक की बैठक में दिए। बैठक में शिक्षण सत्र 2020 21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की समीक्षा की गई तथा निःशुल्क गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं पीआईयू द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में भी समीक्षा की गई। बैठक में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों की अतिरिक्त मांग के संबंध में अवगत कराया। संभागायुक्त श्री कियावत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी 7 दिवस में शालाओं की मांग का परीक्षण कर परिवर्तन वाली पुस्तकों के लिए 100 प्रतिशत एवं जिन पुस्तकों में परिवर्तन नहीं हुआ है उनकी पूर्ति संभवतः गत वर्ष की शेष बची उस कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पुस्तकों से करने, नामांकन बढ़ने के कारण वास्तविक मांग पत्र संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लोक शिक्षण संचालनालय एवं एक प्रति मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को भेजने के निर्देश दिए गए।

नवंबर तक गणवेश तैयार करें

संभागायुक्त श्री कियावत ने निःशुल्क गणवेश वितरण के संबंध मे जिला परियोजना समन्वयकों को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से संपर्क कर गणेश बनाने हेतु स्व सहायता समूह की क्षमता का आकलन करने एवं माह नवंबर 2020 तक गणवेश तैयार कराने के निर्देश भी दिए। श्री कियावत ने निर्देशित किया जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते मे राज्य स्तर से वन विलक के माध्यम से जारी राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण नहीं पहुंची है उनके बैंक खाते का पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपडेशन सात दिवस में पूरा करना सुनिश्चित करें।

होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव भेजे तथा अशासकीय शालाओं द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर उनकी मान्यता समाप्त करने, नियमानुसार अर्थ दंड दिए जाने का प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जाए। बैठक में संभागायुक्त ने पीआईयू द्वारा कराए जा रहे समस्त निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर उनमें पाई गई कमियों से पीआईयू को लिखित में अवगत कराने तथा निर्माणाधीन सभी विद्यालयों का विद्यालयवार निरीक्षण प्रतिवेदन 10 दिवस में भेजने के निर्देश दिए।

हर मंगलवार सभी पटवारी अपने कार्यालयों में बैठेंगे : कलेक्टर

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए है कि जिले के समस्त राजस्व क्षेत्रों में हर मंगलवार सभी पटवारी अपने कार्यालयों में बैठेंगे और आम जनता की समस्या को सुनेंगे। साथ ही नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों पर कार्यवाही भी करेंगे और उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रति सोमवार प्रस्तुत करेंगे। बुधवार को संपन्न टीएल बैठक में यह निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को कहा कि ऑफिस के पुराने रिकार्ड और फर्नीचर को राइट अप करने की कार्यवाही शुरू करें और जिन रिकार्ड को रखना नियमानुसार जरूरी नहीं है उनको नस्ती कर आवश्यक कार्यवाही करें। दीपावली के पूर्व सभी रिकार्ड का निरीक्षण कर टीप अंकित करें। राजस्व में चल

रहे सीमांकन, बटवारा, डायवर्सन, नामांतरण के प्रकरणों को तुरंत निपटाए, समय-सीमा के अंदर ही प्रकरणों को निराकृत करें। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सभी एसडीएम और तहसीलदार लगातार पटवारी हल्का से रिपोर्ट और उनकी एनओसी भी ले, उसके बाद भी यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पट्टा नवीनीकरण के संबंध में शासन द्वारा जारी नवीन गाइड लाइन का पालन करते हुए कार्यवाही की जाए। सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू के लिए चलाए जा रहें अभियान की जानकारियां लेते रहें।

प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन का धरना आज, विशेष पैकेज की मांग

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश भर में धरना देगा। धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रायवेट स्कूलों को विशेष पैकेज देने की मांग की जाएगी। राजधानी में धरना सुबह दस बजे से नीलम पार्क में शुरू होगा। प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि कोरोना काल में मार्च के महीने से प्रायवेट स्कूल बंद है। अशासकीय स्कूल संचालकों को आय के रूप में केवल एकमात्र फीस ही साधन है। आय का अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। स्कूल की फीस सात माह से आना पूरी तरह बंद है। ऐसे में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी परेशान हैं। स्कूल में काम करने वाला अन्य स्टाफ भी प्रभावित है। संचालकों की हालत तो और भी खराब है। स्कूल के खर्चे जैसे बिजली का बिल, वेतन, पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ियों की किश्त एवं जो लोन लिए गए हैं, उनकी किश्त भी निरंतर आ रही है। आरटीई फीस का भुगतान भी नहीं आ रहा है। कोरोना से अशासकीय विद्यालयों के संचालक सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश में लगभग 45000 स्कूल संचालक एवं आठ लाख कार्यरत शिक्षक तथा अन्य स्टाफ की तरफ ध्यान दिया जाए। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं उनके शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कार्यरत अन्य स्टाफ को सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही अशासकीय विद्यालयों के द्वारा जो भी लोन लिया गया है, उस लोन की अवधि अगले शिक्षा सत्र के लिए बढ़ा दी जाए।

नीलम पार्क में सुबह दस बजे से शुरू होगा धरना

एसबीआइ क्लर्क परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

भोपाल(नरि)। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की वेबसाइट ibps.in पर प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। जो अभ्यर्थी एसबीआइ क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में सफल हुए थे, उन्हें ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी अब एसबीआइ क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी।

सुर्खियों से आगे अंतरिक्ष के लिए खोजी जा रही तकनीकें हमें टिकाऊ विकास देने में मदद कर सकती हैं

अंतरिक्ष में खोज अच्छे भविष्य की उम्मीदें पैदा कर रही है

साधना शंकर

लेखिका और भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी

सितंबर 2020 में यूके के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अपनी खोज प्रकाशित की, इसमें कहा गया कि शुक्र ग्रह के अम्लीय (एसिडिक) माहौल में उन्हें सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जहरीली गैस फॉस्फीन मिली। इससे शोधकर्ता काफी उत्साहित हैं, क्योंकि मंगल की तरह शुक्र ग्रह भी हमारा नजदीक का पड़ोसी है।

60 के दशक की शुरुआत में पहली बार खोज नजदीकी ग्रह मंगल और शुक्र से शुरू हुई। शोधकर्ताओं को वहां की परिस्थितियां चरम सीमा की दिखीं, जो कि हमारे जीवविज्ञान के पूर्व ज्ञान पर आधारित थी और इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन ग्रहों पर जीवन मुमकिन नहीं है। और तब रुचि और शोध का विस्तार सुदूर ग्रहों जैसे बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा और शनि के चंद्रमा 'टाइटन' तक हुआ। जैसे-जैसे अंतरिक्ष में खोज बढ़ी, जैविक शोध भी बढ़ता गया। धरती पर, सूक्ष्म जीवाणुओं की खोज हुई, जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों जैसे न्यूक्लियर वेस्ट, समुद्र की गहराइयों और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी पैनल पर भी जीवित रह सकते हैं। इसलिए शायद मुमकिन है कि हमारे पड़ोसी ग्रहों पर भी जीवन हो!

ब्रह्मांड की सीमाओं और इन पर जीवन की खोज करना एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयास रहा है। अंतरिक्ष के प्रति हमारा आकर्षण साइंस फिक्शन कहानियों और फिल्मों में दिखता है, यह बड़ी उत्सुकता जगाता है। पिछले एक दशक में कई निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में आई हैं।

भारत में भी अंतरिक्ष शोध लगातार बढ़ रहा है। हमारा पहला ग्रहों के बीच का मिशन मंगलयान सितंबर 2014 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और डाटा भेज रहा है। इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' 2022 में छोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। इसरो ने शुक्र ग्रह के वातावरण की केमिस्ट्री जांचने के लिए 2025 में 'शुक्रयान' अभियान की घोषणा की है। जून 2020 में भारत ने निजी क्षेत्रों समेत स्टार्टअप्स के लिए भी अंतरिक्ष गतिविधियां खोल दी हैं।

तो कैसे ये अंतरिक्ष के बारे में खोज हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। हममें से अधिकांश लोग कहेंगे कि वे नहीं करतीं- हम उनके बारे में बिना सोचे-विचारे ही पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में ये खोजें हमारे रोजमर्रा के जीवन को असंख्य तरीकों से प्रभावित करते हैं। अंतरिक्ष खोज ने धरती पर जीवन को बहुत लाभान्वित किया है। अंतरिक्ष खोज में इस्तेमाल अत्याधुनिक तकनीक, सामग्री, रोबिटिक्स, हाईटेक कम्प्यूटिंग ने हमारे जीवन जीने के तरीके को बदलकर रख दिया है। इंटरनेट से लेकर, सोलर पैनल्स, जीपीएस और बेबी फूड से लेकर इंफ्रारेड थर्मामीटर, कैमरा सेंसर्स, ये सभी अंतरिक्ष मिशन के प्रोजेक्ट्स के दौरान विकसित किए गए। अंतरिक्ष में, प्रोजेक्ट्स की आयु और उसका टिकाऊपन सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। दोबारा इस्तेमाल में आने वाले रॉकेट की तकनीक अंतरिक्ष खोज को सस्ता और टिकाऊ बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। जब यह सफल हो जाएगा, तो यह धरती पर हमारी यात्रा के तरीके को बदलकर रख देगा और टिकाऊ विकास को भी प्रेरित करेगा।

चूंकि पूरी मानवता ऐसी महामारी से लड़ रही है, जो पिछली सदी में नहीं देखी, ऐसे में अंतरिक्ष की खोज में किए जा रहे प्रयास हमें अच्छे भविष्य की उम्मीद दिखाते हैं। अगर इंसान मंगल, शुक्र तक पहुंच सकते हैं या सुदूर शनि को खोज सकते हैं या अन्य जीवन का पता कर सकते हैं, तो हम जल्द ही यहां कोरोना वायरस का भी समाधान खोज लेंगे।

तो अब से जब भी अगली बार ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की दिशा में एक और कदम बढ़ने वाली कोई हेडलाइन देखें, तो विश्वास रखें कि धरती पर यह हमारी जिंदगी को भी आज नहीं तो कल जरूर प्रभावित करेगी!

(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)

आपके जीवन की बैलेंस शीट में पुण्य ही प्रॉफिट है

एन. रघुरामन
मैनेजमेंट गुरु
raghu@dbcorp.in

ये होटलवाले मानते थे कि 'खाना बेचना पाप है'! होटल चलाने वाला होने के बावजूद उन्होंने कभी कमरे नहीं बेचे, क्योंकि थे ही नहीं। लेकिन अपने और परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्हें खाना बेचना पड़ता था। लेकिन जब भी वे खाना बेचते, तो उन्हें लगता कि वे पाप इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उनके पिता ऐसा कहते थे। इसीलिए उन्होंने पाप का बोझ कम करने का तरीका निकाला। इससे उन्हें लगता था कि चित्रगुप्त के साथ हिसाब में मदद मिलेगी, जो हमारे पुराणों के मुताबिक जीवन की बैलेंस शीट बनाने वाले चीफ़ एकाउंटेंट हैं।

इस मंगलवार रात, के. नारायणस्वामी उर्फ चंदन की हार्टअटैक से मृत्यु हो गई। वे मुंबई के प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय रेस्त्रां 'मणीज़ लंच होम' के मालिक थे। अगर आप उनके पिता के नाम पर बने इस छोटे रेस्त्रां के सामने से गुजरेंगे तो सांबर, फिल्टर कॉफी और अन्य दक्षिण भारतीय व्यंजनों की खुशबू आपको खींच लेगी। लेकिन सांबर उनकी खासियत थी। जिस तरह आज स्टारबक्स और कैफे कॉफी डे, कॉफी की खुशबू से आकर्षित करते हैं, उसी तरह गुजरने वालों को खुशबू से आकर्षित करने की कला चंदन ने दशकों पहले सीख ली थी। यानी जब ये देशी-विदेशी ब्रांड जन्मे भी नहीं थे, तब चंदन ये कला जानते थे। जैसे आज की पीढ़ी कहती है, 'चलो सीसीडी या स्टारबक्स पर मिलते हैं', वैसे ही अपने लड़कपन के दिनों में हमारी भी मिलने की जगह थी, जिसे हम 'मणि' कहते थे। उस समय वहां मिलने का कारण आज की पीढ़ी जैसा नहीं था। हमारे पास पैसे नहीं होते थे और जो भी पैसा बचता था, उससे पेट भरने के लिए हम 'मणि' ही जाते थे।

ऐसा इसलिए क्योंकि वे न सिर्फ हर नाश्ते के ऑर्डर के साथ मुफ्त सांबर और चटनी देते थे, बल्कि आप जितना चाहें, उतना सांबर-चटनी ले सकते थे। जब हम युवा उनके छोटे से रेस्त्रां में घुसते, वे समझ जाते कि हम उनकी सांबर की बाल्टी लूट लेंगे। वे धीरे से रसोई में चले जाते। कभी-कभी हम सोचते थे कि वे सांबर में गरम पानी मिला देंगे। लेकिन हम गलत थे। वे दरअसल यह सुनिश्चित करने जाते थे कि सांबर में धनिया और हींग की जबरदस्त खुशबू आए और शेफ से चटनी में और नारियल डालने को कहते थे। दरअसल मेरे एक दोस्त से उन्होंने कहा भी था, 'ये युवा गरीब हैं, संघर्षरत हैं, लेकिन ईमानदार हैं। अगर हम खाने की गुणवत्ता में उन्हें धोखा देंगे तो वे समाज को धोखा देने के बारे में सोचेंगे। जैसे हम साल-दर-साल आर्थिक रूप से मजबूत होते गए, ये युवा भी सफल होंगे। वहां पहुंचने के लिए हमें उन्हें खाना देना होगा। यही एक तरीका है जिससे मैं खाना बेचने के अपने पाप को कम कर सकता हूं।'

चूंकि हर दक्षिण भारतीय त्योहार (जो ढेर सारे हैं) पर हम अपने गृहनगर नहीं जा सकते थे, इसलिए तब वे मेन्यू थोड़ा बदलकर उसमें सामान्य इडली, मेदू वड़ा, मैसूर बोंडा और डोसा की जगह कुछ त्योहारी व्यंजन जोड़ देते। नियमित आने वालों के लिए, नए ग्राहकों से छिपकर मिठाई दो बार परोसी जाती, यह कहते हुए कि 'तुम्हें मां के हाथ का खाना याद आ रहा होगा।' एक पल के लिए वे सभी की आंखों के सामने उनकी मां के चेहरे लाकर, उन्हें भावुक कर देते थे। यह अहसास वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने माता-पिता से दूर अकेले रहकर जीवन जिया है।

चंदन की तरह, हम सभी को भी अपने जीवन में एक विश्वास लाने और उसे ध्यान में रखकर कार्य करने की जरूरत है क्योंकि इससे हमारा अंतिम प्रॉफिट (पढ़ें पुण्य) संभल जाता है और जीवन की बैलेंस शीट चमक उठती है।

फंडा यह है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको हमेशा याद रखे, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास जीवन में एक ऐसा विश्वास जरूर हो, जिसे ध्यान में रखकर आप सारे कार्य करें।

कृषि व गृह विज्ञान विषय के शिक्षकों की नौकरी संकट में

ग्वालियर/भोपाल • डीबी स्टार

दो दशक पहले संविदा अध्यापक बने कृषि और होम साइंस विषय के डिग्रीधारी सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। नए भर्ती नियम के कारण इनका शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हो पा रहा है। दरअसल शिक्षक कैडर समाप्त करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को महकमे में शामिल करने के लिए 'मप्र राज्य शिक्षा सेवा' नामक नया कैडर बनाया है। शैक्षणिक संवर्ग के लिए सेवा-शर्तें और भर्ती नियम-2018 बनाए। यानी, जहां अब नई भर्ती इसी कैडर में नए नियमों के तहत होगी, वहीं 20 साल पहले अध्यापक बने शिक्षकों का भी इसी कैडर के अनुरूप विषयवार पदांकन किया जा रहा है।

इस नियम के कारण होम साइंस, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग में स्नातक अध्यापकों का मामला अटक गया है। ये तीनों विषय स्कूलों में आठवीं तक नहीं पढ़ाए जाते हैं। ऐसे में ये शिक्षक किसी अन्य विषय के शिक्षक बने हैं तो उन्हें नए नियम (गजट नेटिफिकेशन) के हिसाब से मान्यता नहीं मिल रही है। जुलाई 2018 में जारी नोटिफिकेशन में हुई त्रुटि में सुधार के लिए अब तक संशोधन नहीं हुआ है। इधर, प्रभावित शिक्षकों को नौकरी जाने का डर है क्योंकि विभाग के नए नियम अनुसार इनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध मानी जा सकती है।

कन्या हाईस्कूल के कक्षों का किया भूमिपूजन

पीपुल्स संवाददाता • खिरकिया

शिक्षा ही एक मात्र साध्य है, जिससे समाज गांव देश की प्रगति संभव है। सरकार ने बेटियों की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। इसमें सभी लोग सहयोग करें। यह बात क्षैत्रीय विधायक एवं कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा स्थानीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत 62 लाख की लागत से बनने वाले पांच कक्षों के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। पटेल ने कहा सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, मातृशक्ति का उपयोग समाज निर्माण एवं विकास ही रहा है। इस अवसर पर कन्या माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक प्रदीप रिछारिया द्वारा शाला की सुरक्षा के लिए 130 मीटर बॉउन्ड्रीवाल की मांग रखी। जिसे मंत्री पटेल ने 5 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। पटेल ने कहा आपकी हर मांगो का परिक्षण कर राशि स्वीकृत की जावेगी। उन्होने निर्माण ठेकेदार से यह अपेक्षा की वे समय सीमा में तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष गोलू राजपूत, वरिष्ठ भा.ज.पा. नेता शंकरसिंह राजपूत, गंगाविशन मुनीम, जयंत नागड़ा, भरत हेड़ा, विजय सोमानी, जिला शिक्षा अधिकारी डी. एस. रघुवंशी, बीईओ अजपसिंह राजपूत, बी.आर.सी. जी.आर. चौरसिया, पर्यवेक्षक पौढ़ शिक्षा उमाकान्त वर्मा आदि उपस्थित थे।

12 जिलों में एनसीटीई के 7 कोर्सों में नहीं हुआ कोई एडमिशन

बीएड में ग्वालियर जिले में सर्वाधिक स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन, भोपाल दूसरे स्थान पर

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एज्युकेशन)के बीएड सहित आठ कोर्सों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग चलाई जा रही है। इसमें प्रदेश के 12 जिलों में बीएड में तो प्रवेश हुए हैं लेकिन अन्य 7 कोर्सों में एक भी एडमिशन नहीं हुए हैं।

इधर, बीएड के कोर्सों में एडमिशन में ग्वालियर जिला प्रदेश में सबसे आगे है, जबकि भोपाल में दूसरे स्थान पर है। ग्वालियर जिले में बीएड कोर्स में सबसे अधिक 6267 प्रवेश और भोपाल में 5227 प्रवेश हुए हैं। वहीं इंदौर में 3051 और जबलपुर में 2438 प्रवेश अब तक हुए हैं। इसके अलावा सतना, सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा जिलों में यूजी में दस हजार से अधिक प्रवेश हुए हैं।

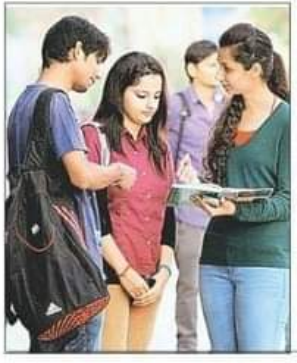

प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जिनमें एनसीटीई के आठ कोर्सों में से सिर्फ बीएड में ही एडमिशन हुए हैं। शेष 7 कोर्सों में जीरो एडमिशन है। इनमें अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, आगर मालवा समेत अन्य जिले शामिल हैं।

बीएड में अब तक 52 हजार 476 प्रवेश हो चुके हैं। वहीं बीएलएड में प्रवेश की संख्या सैंकड़ा तक भी नहीं पहुंच सकी है। यहां सिर्फ 78 प्रवेश हुए हैं। एमपीएड में 341 और बीएडएमएड में 164 प्रवेश हुए हैं। इसके अलावा बीपीएड में 1191, एमएड में 2444, बीएबीएड में 1996 और बीएससी बीएड में 1486 प्रवेश हुए हैं।

एनसीटीई के कोर्स में एडमिशन की स्थिति

कोर्स	कुल सीटें	फर्स्ट राउंड	सेकंड राउंड	थर्ड राउंड	एक्स्ट्रा राउंड	खाली सीटें
बीएड	51700	14750	11058	8959	2472	14761
एमएड	2650	299	550	411	145	1245
बीपीएड	1650	191	407	257	31	764
एमपीएड	365	126	71	46	14	108
बीएबीएड	3250	452	540	454	122	1642
बीएससीबीएड	2500	302	386	341	70	1401
बीएडएमएड	250	41	38	41	03	130
बीएलएड	100	निरंक	36	09	03	52

बीएड की 75 फीसदी सीटें फुल, अन्य कोर्सों को नहीं मिल रहे स्टूडेंट

एनसीटीई के आठ कोर्स में खाली 62 हजार 465 सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त राउंड की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एनसीटीई के सभी आठों कोर्स में सबसे अधिक 75 फीसदी एडमिशन हुए हैं। बीएड में खाली 51700 सीटों में से 14 हजार 761 सीटें खाली हैं। बीपीएड सहित अन्य कोर्स में आधी सीटें अब भी खाली हैं। बीएड में अधिक एडमिशन की मुख्य वजह इसका रोजगारपरक होना और स्वयं का शिक्षण संस्थान शुरू करने जैसी खूबियां होना है। एनसीटीई के कोर्स में एडमिशन के अतिरिक्त राउंड में बीएड में लगभग 25 हजार छात्र-छात्राओं ने एडमिशन लिया है।

आईसीएआई की परीक्षाएं नवंबर से, जारी हुआ शेड्यूल

21 नवंबर से 14 दिसंबर तक का टाइम टेबल

रिपोर्टर • IamBhopal

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस साल की आईसीएआई सीए परीक्षा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। पहले यह परीक्षा 1 से 18 नवंबर के बीच आयोजित होनी थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 21 नवंबर से 14 दिसंबर कर दिया गया है। अब इस तारीख को सीए परीक्षा आयोजित होगी। पेपर सिंगल शिफ्ट में आयोजित होगा और दोपहर में दो बजे से शुरू होगा।

अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

आईसीएआई की सीए नवंबर परीक्षा 2020 का बदला शेड्यूल देखने के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट **icai. org.** विजिट करना होगा। अन्य जानकारियों के लिए चैप्टर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन

8, 10, 12 और **14** दिसंबर

इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन पुरानी स्कीम के अंतर्गत

ग्रुप 1 : **22, 24, 26** और **28** नवंबर

ग्रुप 2 :, **3** और **5** दिसंबर

इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन नई स्कीम के अंतर्गत

ग्रुप 1 : **22, 24, 26** और **28** नवंबर

ग्रुप 2 :, **1, 3, 5** और **7** दिसंबर

फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन पुरानी स्कीम के अंतर्गत

ग्रुप 1 : **21, 23, 25** और **27** नवंबर

ग्रुप 2 : **29** नवंबर **2020, 2, 4** और **6** दिसंबर

इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन

इंटरनेशनल ट्रेड लॉज एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट वन एग्जामिनेशन

ग्रुप 1 : **21** और **23** नवंबर

ग्रुप 2 : **25** और **27** नवंबर

इंटरनेशनल टैक्सेशन एसेसमेंट टेस्ट

21 और **23** नवंबर

यूजी-पीजी के एडमिशन में इंदौर अव्वल, भोपाल दूसरे स्थान पर

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

यूजी पीजी में अभी तक हुए एडमिशन के मामले में राजधानी दूसरे नंबर पर है, जबकि इंदौर प्रदेश में अव्वल है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी, पीजी प्रवेश के लिए प्रक्रिया का अतिरिक्त व अंतिम चरण चलाया जा रहा है। अभी तक इंदौर में यूजी में 30 हजार 866 और पीजी में 5467 प्रवेश हुए हैं। जबकि भोपाल में यूजी में 17 हजार 356 और पीजी में 4718 स्टूडेंट्स ने ही प्रवेश लिया है। इसके बाद यूजी में पांच अंकों के सबसे आगे सागर में 13275, उसके बाद जबलपुर में 12999, ग्वालियर में 12877 और छिंदवाड़ा में 11448 एडमिशन हुए हैं।

थर्ड सीएलसी राउंड तक 44 हजार 695 प्रवेश: यूजी में सीएलसी का थर्ड राउंड चल रहा है। इसमें 1 लाख 18 हजार 815 स्टूडेंट को मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की गई थीं। इनमें से 44 हजार 695 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। स्टूडेंट 26 तक फीस जमा कर सकते हैं। वहीं पीजी में थर्ड राउंड की सीएलसी में 16 हजार 711 नए स्टूडेंट्स पंजीयन और 71 हजार 307 ने चॉइस फिलिंग की है। 14, 395 ने सत्यापन कराया है।

विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग निदेशक को बदला, क्लर्क का तबादला

उज्जैन | विक्रम विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक को कुलसचिव ने बुधवार को बदल दिया। विभाग के क्लर्क का तबादला कर दिया है। कुलसचिव यूएन शुक्ला के अनुसार डॉ. निश्चल यादव, निदेशक शारीरिक शिक्षा विभाग को संबंधित प्रभार से मुक्त करते हुए डॉ. आरके अहिरवार, अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग को निदेशक बनाया है। क्रीड़ा विभाग के क्लर्क दीपक दुबे का तबादला वनस्पति शाखा में कर दिया है।

कोर्सवर्क की परीक्षा ऑनलाइन कराने के लिए छात्र पहुंचे कुलपति सचिवालय

ग्वालियर| पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा जल्द आयोजित कराने की मांग को लेकर छात्र-छात्राएं बुधवार को कुलपति सचिवालय पहुंच गए। यहां पर उन्होंने अधिकारियों से कोर्स वर्क की परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से कराने की मांग की। भोपाल में बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

पीएचडी में 2018-19 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कोर्स वर्क परीक्षा आयोजित होना है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। बुधवार को यूनिवर्सिटी पहुंचे छात्रों का कहना था कि परीक्षा देरी से कराए जाने की वजह से उनका शोध भी देरी से शुरू हो पाएगा। इसलिए जल्द ही ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। छात्र-छात्राओं ने इसके लिए बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा इसी पद्धति से परीक्षा कराए जाने का उदाहरण भी दिया। छात्रों का कहना था कि 10 दिन में इस संबंध में निर्णय नहीं किया गया तो राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
E-mail : mpbse @ mp.nic.in Website : www.mpbse.nic.in
☎ कार्या :- (0755) 2551166-71, Fax (0755) 2551499, 2552061
भोपाल दिनांक 21/10/2020

प्रेस विज्ञप्ति

मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हा.से. परीक्षाओं में वर्ष 2021–22 से विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान समाप्त।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में वर्ष 2020–21 से कक्षा 9वीं एवं 11वीं कक्षाओं में अब विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा का प्रावधान समाप्त किया गया है। इसके स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट एवं सामान्य भाषा के अलग–अलग पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र न होकर केवल 01 भाषा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

01 हिन्दी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर हिन्दी भाषा।
02 अंग्रेजी विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा।
03 संस्कृत विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर संस्कृत भाषा।
04 उर्दू विशिष्ट एवं सामान्य के स्थान पर उर्दू भाषा।

इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में भी अब विशिष्ट भाषा एवं सामान्य भाषा के स्थान पर अब मात्र संबंधित विषय का उपरोक्तानुसार एक ही प्रश्न पत्र होगा।

साथ ही हायर सेकण्डरी के वाणिज्य एवं कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय हेतु Central Board of Secondary Education (CBSE) अनुसार समान पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। अर्थशास्त्र विषय का पाठ्यक्रम वाणिज्य एवं कला संकाय हेतु समान रहेगा।

उक्त व्यवस्था के संबंध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन,द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है।

21/10/20

जनसंपर्क अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.
भोपाल